अंतरिम बजट 2009-2010 की मुख्य विशेषताएं

प्रस्तावना

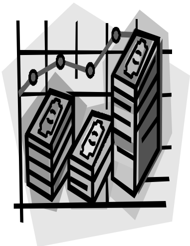

- सकल घरेलू उत्पाद में वित्त वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक पहले चार वर्षों में 7.5 प्रतिशत, 9.5 प्रतिशत, 9.7 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसमें पहली बार लगातार तीन वर्षों के दौरान 9 प्रतिशत से अधिक की सतत वृद्धि दर्ज हुई है। इस अवधि में वृद्धि वाले क्षेत्र कृषि, सेवा, व्यापार और निर्माण सहित विनिर्माण रहे।
- राजकोषीय घाटा 2003-04 में 4.5 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में 2.7 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 3.6 प्रतिशत से कम होकर 2007-08 में 1.1 प्रतिशत हो गया।
- सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में घरेलू निवेश दर 2003-04 में 27.6 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 39 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि के दौरान सकल घरेलू बचत दर 29.8 प्रतिशत से बढ़ कर 37.7 प्रतिशत हो गई।
- कृषि का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कृषि में सकल पूंजी निर्माण 2003-04 में 11.1 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 14.2 प्रतिशत हो गया।
- कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2003-04 में 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 12.5 प्रतिशत हो गया।

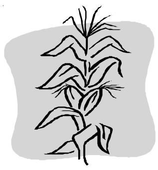

- कृषि की वार्षिक वृद्धि दर 2003-04 से 2007-08 के दौरान 3.7 प्रतिशत बढ़ गयी। इस अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में हर वर्ष लगभग 10 मिलियन टन की वृद्धि हुई और यह 2007-08 में बढ़कर 230 मिलियन टन हो गया। यह अब तक सबसे अधिक है।
- जबकि विनिर्माण क्षेत्र में 2004-05 से 2007-08 की अवधि में 9.5 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की, वहीं संचार तथा निर्माण क्षेत्र की विकास दर प्रति वर्ष क्रमशः 26 प्रतिशत तथा 13.5 प्रतिशत रही।

- वर्ष 2004-05 से 2007-08 की अवधि में, निर्यात अमरीकी डालर मूल्य में 26.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक विकास दर से बढ़ा, विदेश व्यापार 2003-04 में स.घ.उ. के 23.7 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 35.5 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2008-09 के लिए दृष्टिकोण

- 2007 में शुरू हुए वैश्विक राजकोषीय संकट के कारण अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ने के बावजूद, चालू वर्ष में स.घ.उ. में 7.1 प्रतिशत विकास दर विश्व की सबसे तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्था में दूसरे स्थान पर है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी की नकारात्मक घटना का सामना करने के लिए 7 दिसम्बर, 2008 तथा 2 जनवरी, 2009 को राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की गयी जिनमें मांग बढ़ाने और सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय बढ़ाने के लिए कर राहत दी गयी।

- सरकार ने अगस्त, 2008 से जनवरी 2009 तक 70,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 37 ढांचागत परियोजनाओं को अनुमोदित किया।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली के तहत, 67,700 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की 54 ढांचागत परियोजनाओं को सैद्धांन्तिक मंजूरी दी गयी अथवा अंतिम रुप से अनुमोदित किया गया और 2008-09 में 27,900 करोड़ रुपए की लागत वाली 23 परियोजनाओं को व्यवहार्यता अन्तराल निधिपोषण के लिए अनुमोदित किया गया।

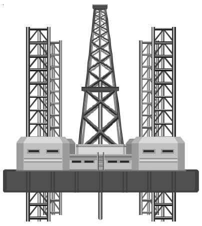

- इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) आगामी लगभग अठारह महीनों के दौरान पीपीपी परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक बैंक ऋणों का 60 प्रतिशत तक पुनर्वित्तपोषण करेगी जिसमें अवसंरचनाओं में 1,00,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश होगा।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकदी आरक्षित निधि अनुपात, सांविधिक नकदी अनुपात और मुख्य नीतिगत दरों में कटौती करने जैसे मौद्रिक सहजता एवं नकदी बढ़ाने संबंधी अनेक उपायों के अतिरिक्त, सरकार ने विशिष्ट उपाय किए हैं जिनमें श्रम प्रधान निर्यातों के लिए निर्यात ऋण का विस्तार, लदान-पूर्व और लदानोत्तर ऋण की उपलब्धता में सुधार, सीमांत उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी के लिए अतिरिक्त आबंटन एवं निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं, और निर्यात शुल्क हटाना एवं कुछ मदों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल हैं। निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही प्रक्रियात्मक समस्याओं का समाधान करने हेतु सचिवों की एक समिति गठित की गयी है।

- 2007-08 के दौरान, रिकार्ड 32.4 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ। वैश्विक वित्तीय संकट के होते हुए भी, अप्रैल-नवम्बर, 2008 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 23.3 बिलियन अमरीकी डालर रहा, जो 2007 में इसी अवधि की तुलना में 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- मौजूदा वर्ष और वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान, अत्यावश्यक मांग बढ़ाने के लिए एफआरबीएम लक्ष्यों में ढील दी गई है। तथापि, मध्यावधिक उद्देश्य शीघ्रातिशीघ्र राजकोषीय समेकन की ओर लौटना है।

प्रयास और उपलब्धि

कृषि

- वर्ष 2003-04 से 2008-09 की अवधि में, कृषि के लिए आयोजना आबंटन 300 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर बढ़ाकर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए के परिव्यय से 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई।

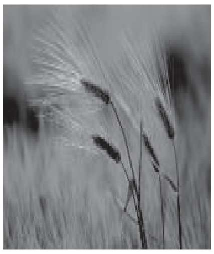

- कृषि ऋण संवितरण 2003-04 में 87,000 करोड़ रुपए से तीन गुणा बढ़ा कर 2007-08 में 2,50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया।
- अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए, लगभग 13,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से 25 राज्यों में पुनरुद्धार पैकेज कार्यान्वित करना।

- वर्ष 2009-10 में ब्याज सहायता देना जारी रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान 3 लाख रुपए तक के अल्पावधिक फसल ऋण 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज-दर पर प्राप्त करें।
- कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 यथानिर्धारित 30 जून, 2008 तक क्रियान्वित की गई। 3.6 करोड़ किसानों को 65,300 करोड़ रुपए की ऋण माफी/ऋण राहत।

- पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च खरीद लागतों और उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बावजूद, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्यों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों (बी.पी.एल) और अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणियों के मामले में जुलाई 2000 के स्तर पर और गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल) की श्रेणी में जुलाई 2002 के स्तर पर रखा गया है।

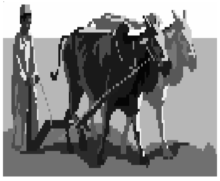

- 2003-04 में, साधारण किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 550 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर फसल वर्ष 2008-09 में 900 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। गेंहू के मामले में, यह 2003-04 में 630 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2009 में 1080 रुपए प्रति क्विंटल किया गया।

ग्रामीण विकास

- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की आधारभूत निधि को वर्ष 2003-04 के 5500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में 14,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। विगत तीन वर्षों के लिए ग्रामीण सड़कों के संबंध में पृथक विंडो का सृजन किया गया, जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिए 4,000 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि का प्रावधान था।

- इंदिरा आवास योजना के तहत 2008-09 तक 60 लाख मकानों का निर्माण किया जाना था, इसके मुकाबले 60.12 लाख मकानों का निर्माण वर्ष 2005-06 से दिसम्बर, 2008 के बीच किया गया।
- पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना (पीईएआईएस) का विस्तार, किया जाना प्रस्तावित है।

- आम आदमी को डाक घरों के जरिए नई प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएँ प्रदान करने हेतु 'परियोजना एरो' डाकघरों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। इस परियोजना को सरकार द्वारा पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी।

शिक्षा

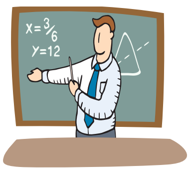

- माध्यमिक स्तर पर सबको शिक्षा सुलभ कराने हेतु वर्ष 2008-09 में केन्द्र प्रायोजित एक नई योजना सहित प्रमुख पहलें शुरू की गयी है।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतर शिक्षा संबंधी परिव्यय में 9 गुणा वृद्धि की गई है। 15 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अध्यादेश प्राख्यपित। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब और गुजरात में 6 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) ने 2008-09 में अपना कार्य आरंभ कर दिया है। मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में दो और आईआईटी के 2009-10 में अपने शैक्षिक सत्र आरंभ करने की संभावना है। पूर्व में घोषित 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसईआर) में शिक्षण कार्य आरंभ हो गया है, विजयवाड़ा और भोपाल स्थित नियोजन और वास्तुकला के 2 नए विद्यालयों ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रस्तावित छः नए भारतीय प्रबंध संस्थानों में से, चार में शैक्षिक वर्ष 2009-10 में शिक्षण कार्य आरंभ होने की संभावना है। ये संस्थान हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और तमिलनाडु में स्थित हैं।

- सरकार द्वारा शिक्षा ऋण योजना में संशोधन किए जाने के कारण, 31 मार्च, 2004 के लाभभोगियों की संख्या 3.19 लाख और 4,500 करोड़ रुपए की बकाया ऋण राशि बढ़कर 30 सितम्बर, 2008 को लाभभोगियों की संख्या 14.09 लाख और बकाया ऋण राशि 24,260 करोड़ रुपए हो गई।

- 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में उन्नत किया गया। 1,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आधारभूत निधि के साथ जुलाई, 2008 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की गई।

सामाजिक क्षेत्र

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की प्राधिकृत पूँजी 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए की जा रही है।
- अस्वच्छ व्यवसायों में रत लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और 2008-09 में छात्रवृत्ति की दरें दोगुनी कर दी गई हैं। वार्षिक तदर्थ अनुदान भी पहले की दरों की अपेक्षा पर्याप्त रूप से लगभग 50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

- राष्ट्रीय महिला कोष को, इसकी प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर सुदृढ़ किया जाएगा।
- प्रियदर्शिनी परियोजना' ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रम है। बिहार के मधुबनी और सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली और सुल्तानपुर जिलों में इसे प्रायोगिक परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।
- मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 146 लाख व्यक्ति लाभान्वित।

- दो नई योजनाएं - 40-64 आयु वर्गों के बीच की विधवाओं को 200 रुपए पेंशन उपलब्ध कराने हेतु 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना' और गम्भीर रूप से निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन उपलब्ध कराने हेतु 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना'।
- 18-40 आयु वर्ग की विधवाओं को आईटीआई, महिला आईटीआई और राष्ट्रीय/क्षेत्रीय महिला आईटीआई में प्रवेश में प्राथमिकता देना। सरकार उनके प्रशिक्षण की लागत वहन करेगी तथा 500 रुपए प्रतिमाह वृत्तिका प्रदान करेगी।

- 22 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने असंगठित क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरम्भ की और 60.32 लाख लोगों को 'आम आदमी' बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया।

सरकारी क्षेत्र के उद्यम

- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कारोबार 2003-04 में 5,87,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2007-08 में 10,81,000 करोड़ रुपए हो गया और लाभ 53,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 91,000 करोड़ रुपए हो गया, हानि उठाने वाले उद्यमों की संख्या 2003-04 में 73 से घटकर 2007-08 में 55 हो गयी। लाभ कमाने वाले उद्यमों की संख्या इसी अवधि के दौरान 143 से बढ़कर 158 हो गयी।
- सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन को जून, 2007 में मंजूरी दी है।
- केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त आय में राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की और 31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार 1,815 करोड़ रुपए थी।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार

■ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां 31 मार्च, 2004 को 7.8 प्रतिशत से गिरकर 31 मार्च, 2008 को 2.3 प्रतिशत हो गयी।

■ ऋणात्मक निवल सम्पत्ति वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलयन और पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के फलस्वरुप 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 85 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मिला दिया गया है। 31 दिसम्बर, 2008 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण हेतु 652 करोड़ रुपए का अंशदान किया गया।

■ पिछले चार वर्षों में प्रतिभूति बाजारों को सुदृढ़ व व्यापक बनाने और इन बाजारों के विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

■ कम्पनी अधिनियम, 1956 का व्यापक पुनरीक्षण करते हुए कम्पनी विधेयक 2008, संसद में पेश किया गया है ताकि अन्तरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सर्वोत्तम परम्पराएं अपनायी जा सकें।

कर प्रयास

■ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर-प्रणालियों में व्यापक सुधार किए गए हैं ताकि कर प्रशासन अपनी कार्यात्मक क्षमता बढ़ा सके और बेहतर कर भुगतन सेवाएं उपलब्ध कराने से अनुपालन में तेजी लायी जा सके। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की दरों को भी युक्तियुक्त बनाया गया है जिससे 1 अप्रैल, 2010 से इनके स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर को पूरी तरह अपनाया जा सके।

■ देश की समुद्री सीमाओं के पार से निषिद्ध वस्तुओं की आवाजाही को रोकने के लिए सीमाशुल्क विभाग के लिए 109 समुद्री जहाजों के अधिग्रहण की स्वीकृति दी है।

प्रशासनिक सुधार

■ केन्द्र और कई राज्यों में सूचना के अधिकार के अधिनियमन से लोक सेवकों में बेहतर जवाबदेही लाना।

■ सरकार द्वारा स्वीकृत, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों सहित 45 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 38 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ हुआ है।

संशोधित अनुमान

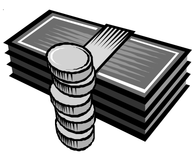

■ बजट अनुमान 2008-09 में 7,50,884 रुपए का कुल अनुमान था, जिसे संशोधित अनुमान 2008-09 में 9,00,953 रुपए किया गया। यह 1,50,069 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है।

■ आयोजना व्यय, ब.अ. 2008-09 में 2,43,386 करोड़ रुपए से बढ़कर सं.अ. 2008-09 में 2,82,957 करोड़ रुपए हो गया।

■ ब.अ. 2008-09 की तुलना में आयोजना-भिन्न व्यय सं.अ. 2008-09 में 1,10,498 रुपए की वृद्धि हुई है।

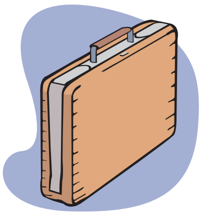

- सं.अ. 2008-09 के सम्बन्ध में कर भिन्न राजस्व 95,785 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2008-09 में 96,203 करोड़ रुपए हो गया।
- ब.अ. 2008-09 के 6,87,715 करोड़ रुपए की तुलना में मुख्यतया भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के प्रभाव का सामना करने के लिए सक्रिय वित्तीय उपाय शुरु किए जाने के कारण कर संग्रहण का सं.अ.6,27,949 करोड़ रुपए रखा गया।
- 55,184 करोड़ रुपए (स.घ.उ. का 1 प्रतिशत) के बजट आंकड़े की तुलना में संशोधित राजस्व घाटा 2,41,273 करोड़ रुपए (स.घ.उ. का 4.4 प्रतिशत) होने का अनुमान है।
- राजकोषीय घाटे के ब.अ. 2008-09 में 1,33,287 करोड़ रुपए (स.घ.उ. का 2.5 प्रतिशत) से 3,26,515 करोड़ रुपए (स.घ.उ. का 6 प्रतिशत) बढ़ने का अनुमान है।

बजट अनुमान

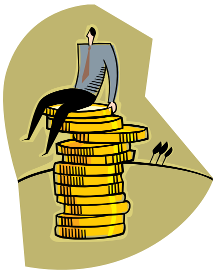

- वित्त वर्ष 2009-10 के लिए 9,53,231 करोड़ रुपए का कुल व्यय अनुमानित है। आयोजना व्यय 2,85,149 करोड़ रुपए और आयोजना-भिन्न व्यय 6,68,082 करोड़ रुपए अनुमानित है।
- ब.अ. 2008-09 की तुलना में आयोजना ब.अ. 2009-10 में ग्रामीण विकास विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, रेल, विद्युत मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को ग्रामीण एवं अवसंरचना विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता बढ़ाई गई है। साथ ही साथ, राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी करने के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को अधिक आवंटन दिया गया है।
- वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 30,100 करोड़ रुपए आवंटित। 2008-09 में 138.76 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन, जिसमें 3.51 करोड़ परिवारों को पहले ही रोजगार दिया जा चुका है।

- सर्वशिक्षा अभियान के तहत लगभग 98 प्रतिशत बस्तियों को प्राथमिक विद्यालयों द्वारा शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 2003-04 और 2008-09 के बीच 571 प्रतिशत आवंटन बढ़ाया गया। 2009-10 के लिए 13,100 करोड़ रुपए का आवंटन करने का प्रस्ताव है।

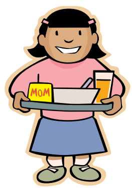

- वर्ष 2009-10 में मध्याह्न भोजन योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए आवंटित।
- एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के लिए 2009-10 में प्रस्तावित आवंटन 6,705 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत बच्चों के विकास को मानीटर करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाल विकास के नए मानक अपनाए गए।
- जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2008 तक 39,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 386 परियोजनाएं स्वीकृत। 2009-10 के लिए इस कार्यक्रम हेतु 11,842 करोड़ रुपए का आबंटन प्रस्तावित।
- वर्ष 2009-10 के लिए राजीव गांधी ग्रामीण पेय जल मिशन के लिए 7,400 करोड़ रुपए, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 1,200 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,070 करोड़ रुपए और भारत निर्माण के लिए 40,900 करोड़ रुपए आवंटित।

- भारतीय यूनिक पहचान प्राधिकरण के लिए 2009-10 की वार्षिक योजना में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।

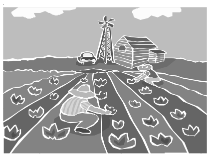

- 14,000 करोड़ रुपए की निधि से प्रस्तावित आरआईडीएफ-XV और ग्रामीण सड़कों के लिए 4,000 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि से अलग विंडो जारी रखना।
- कतिपय रोजगारपरक क्षेत्रों जैसे - वस्त्र उद्योग (हथकरघा और हस्तशिल्प सहित) कालीन, चर्म, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 31 मार्च, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक लदान-पूर्व तथा लदान-पश्च ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय खर्च।
- सरकार अगले दो वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको का पुनः पूंजीकरण करेगी ताकि बैंक परिसम्पत्ति 12 प्रतिशत का पूंजी सम्बद्ध जोखिम भारांश परिसम्पत्ति रखने में समर्थ हो सके।

- रक्षा के लिए आवंटन बढ़ाकर 1,41,703 करोड़ रुपए किया गया जिसमें पूंजी व्यय के लिए 54,824 करोड़ रुपए हैं।
- खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सहित प्रमुख सब्सिडियों का अनुमान 95,579 करोड़ रुपए।
- वित्त वर्ष 2009-10 के लिए केन्द्र का अनुमानित निवल कर राजस्व 5,00,096 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय 8,48,085 करोड़ रुपए, राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत अनुमानित और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत अनुमानित है।